पानी है तो प्राण हैं

जय चक्रवर्ती
राजभाषा अधिकारी,
आई.टी.आई.लि., रायबरेली (उ.प्र.)

प्रकृति, जीवन के लिए अक्षय अनंत निधियों का कोष है, हवा के बाद पानी इसका अमूल्य रत्न है। जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ सब पानी पर आश्रित हैं। भोजन के बगैर तो प्राणी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, किन्तु पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। न सिर्फ जिन्दा रहने के लिए, अपितु जीवन को चलाने के लिए भी पानी पर हमारी निर्भरता सर्वाधिक है। या यूँ कहें कि जल जीवन की पहली शर्त है। पीने से लेकर नहाने, कपड़े धोने, भोजन पकाने और धरती से खाद्यान्न पैदा करने के लिए हम पग-पग पर पानी के ऋणी हैं। सृष्टि के आरम्भ से लेकर अब तक तमाम वैज्ञानिक प्रगति और अनुसंधानों के बावजूद चाहे और किसी भी चीज का विकल्प खोज लिया गया हो, किन्तु पानी का कोई विकल्प नहीं। ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई।

पृथ्वी पर जो भी जल उपलब्ध है, उसका मूल स्रोत वर्षण अर्थात वर्षा और हिमपात है। चूँकि इसके स्रोत पर किसी का अधिकार नहीं है, अतः हमेशा से ही इसे सार्वजिनक वस्तु या समुदाय की वस्तु माना जाता रहा है। भारत जैसे सहिष्णु और धर्म - कर्म वाले देश में तो जल को देवता मानकर इसकी पूजा की जाती रही है और किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य समझा जाता रहा है। आदि काल से समर्थ और परोपकारी प्रकृति के लोग तथा राजे-महाराजे जगह-जगह तालाब, कुएँ इत्यादि बनवाकर प्राणियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था कराकर यश और पुण्य के भागी बनते रहे हैं। नदियाँ, जो जल की मुख्य संसाधन हैं, हमारे यहाँ सदैव से पूज्य रही हैं। किन्तु तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते नगरीकरण, लोगों के बढ़ते जीवनस्तर और औद्योगिक पूँजीवाद ने धरती के इस अति महत्वपूर्ण तत्व की आत्मा को दूषित करने का आत्मघाती दुष्चक्र प्रारम्भ कर दिया है। औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट जल और कचरे ने नदियों और झीलों को बुरी तरह मैला बना दिया है। शायद यह बहुत कम लोग जानते हैं कि सम्पूर्ण धरती पर मात्र एक फीसदी पीने और सिचाई लायक पानी उपलब्ध है और यह चिंतित करने वाला तथ्य है कि यह

प्रतिशत दिन-प्रतिदन घटता जा रहा है। दुनिया में एक अरब से भी ज्यादा ऐसी जनसंख्या है जो आज प्रदूषित जल पीने को विवश है, और दो अरब से ज्यादा लोग नहाने-धोने के लिए भी आवश्यक पानी से वंचित हैं। हमारे देश में राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, बिहार के आदिवासी- रेगिस्तानी इलाकों में लोगों को बारहों महीने एक-एक बूँद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसके अलावा आबादी के बहुत बड़े हिस्से को कुँओ, तालाबों, नदियों, पोखरों का गंदा जल पीना पड़ता है। न सिर्फ इतना अपितु बहुत बड़ी जनसंख्या के हिस्से खतरनाक प्राकृतिक रसायनों जैसे संखिया, फ्लोराइडयुक्त पानी ही आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ो के अनुसार अकेले बांगलादेश में आधे से ज्यादा आबादी प्रदूषित जल के कारण ही अनेक घातक बीमारियों से ग्रस्त हैं। पश्चिम बंगाल सहित भारत में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक संखिया मिला पानी पीकर लोग गुर्दो और फेफड़ो की बीमारियाँ झेल रहे हैं।

देश के लगभग पचास प्रतिशत गांवों में आज भी स्वच्छ पेय जल उपलब्ध नहीं है। निरन्तर बढ़ती आबादी, शहरी क्षेत्र के अनियंत्रित विस्तार, औद्योगीकरण और जल संरक्षण के प्रति हमारी उदासीनता एवं कुप्रबन्धन के चलते आज पूरी दुनिया के सामने पेयजल एक समस्या के रूप में उपस्थित हो गया है। प्रकारान्तर से इस समस्या ने देश - देश के बीच और एक ही देश में प्रान्तों के बीच कई विवादों को जन्म दिया है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल का विवाद जग जाहिर है। भारत-नेपाल, भारत-पाकिस्तान, भारत-बांगलादेश के मध्य पानी के झगड़े और भारतीय उप महाद्वीप के बाहर सीरिया और टर्की के मध्य फुरात नदी को लेकर सदियों पुराना विवाद पूरी दुनियां को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से प्रभावित करते रहे हैं। यदि समय रहते इनके कारणों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, तो निरन्तर कम हो रही पानी की मात्रा कृषि सहित अनेक क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित करेगी।

भूमि से अंधाधुंध जल की निकासी और पुर्नभरण के अभाव के कारण पृथ्वी के गर्भ में जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। हमारे देश में जल प्रबन्धन की खामियों के चलते वर्षा का लगभग पिच्चासी फीसदी जल समुद्र में जाकर गिरने के कारण व्यर्थ चला जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल सीमित है। इसका वितरण भी समान नहीं है। जल प्रदूषित भी है, अतः सबको आवश्यकता के अनुरूप तथा संतुलित जल उपलब्ध हो सके, इसके लिए

तत्काल जल संरक्षण के उपायों पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से दुनिया में विकसित कहे जाने वाले देश हथियारों और ऐशो आराम की चीजों पर तो अरबों डालर प्रतिवर्ष खर्च करते हैं, किन्तु दुनिया के लिए पीने के पानी की व्यवस्था पर खर्च करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है।

अमेरिका जैसा देश ईराक में अपने सैनिकों की तैनाती पर तो पचास मिलियन डालर प्रति सप्ताह खर्च कर सकता है, किन्तु इराक की जनता के लिए पेय जल की व्यवस्था पर कितना खर्च करता है इसका जवाब स्वयं उसके पास भी नहीं है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में भी सरकार की प्राथमिकताओं में पेय जल की व्यवस्था पर खर्च का क्रम अन्य खर्चो से बहुत नीचे है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में सिचाई की सुविधाओं का बहुत विस्तार हुआ है, फिर भी दो तिहाई कृषि योग्य भूमि अभी भी वर्षा पर निर्भर है। इस तथ्य के बावजूद केन्द्र और राज्य सरकारें जल संरक्षण के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं दिखाई देती।

आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में जहाँ सब कुछ विश्व बैंक के निर्देश पर टिका है, पानी जैसी 'समुदाय की सम्पदा' को बाजारवाद और उपभोक्तावाद के चंगुल में लाने के पक्ष में जोरदार वकालत की जा रही है। कहा जा रहा है कि बिना निजीकरण किए हर व्यक्ति को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है। खरीदकर मिलने वाले जल का दुरूपयोग भी कम किया जाएगा-यह भी तर्क भी दिया जा रहा है। निजी हाथों में यह व्यवस्था जाने से जल आपूर्ति और इसमें प्रयुक्त उपकरणों के नवीनतम तकनीक से युक्त बनाने एवं रखरखाव में आर्थिक समस्याएं भी नहीं आएंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है।

समुदाय की सम्पदा को 'माल' बनाकर बेचने का कार्य कई देशों ने प्रारम्भ भी कर दिया है, किन्तु निजीकरण के अन्य अनुभवों के समान ही यहाँ भी जल आपूर्ति और प्रबन्धन करने वाली कम्पनियों का दृष्टिकोण मानवीय कम, मुनाफा कमाना अधिक है। बोतलबंद पानी का बाजार बेहद मुनाफे का बाजार है- इस संभावना को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन सहित तमाम विकसित देश मुनाफा कमाने की इस होड़ में सक्रिय हो उठे हैं। आँकड़े बताते हैं कि **केवल अमेरिका में प्रतिवर्ष सात अरब डालर का बोतलबंद पानी बिकता है। इस धंधे में होने वाले मुनाफे का अनुमान सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता है कि प्रति गैलन**

बोतलबंद पानी का दाम साधरण नल के पानी की तुलना में साढ़े सात हजार गुना अधिक है। हमारे देश में भी उच्च वर्ग और शहरी मध्यवर्ग के लोग बोतलबंद पानी को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित समझ कर उसकी ओर भाग रहे हैं। शीतल पेय बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीयों की इस नब्ज को पहचानकर हमारे देश में बोतलबंद पानी का कारोबार बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है । किन्तु हाल के कंई सर्वेक्षणों से यह बात पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है कि बोतलबंद पानी भी खतरे से खाली नहीं है। **सुप्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका 'साइंटिफिक अमरीकन' ने 'माइकल शर्मर का लेख छापा है जिसमें कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं तकरीबन पच्चीस फीसदी पानी की आपूर्ति ज्यों का त्यों नल से निकालकर बिना साफ किए ही की गई। बीस फीसदी बोतलबंद पानी में हानिकारक रसायन उपस्थित पाए गए। 103 में से 18 ब्रांडों में बैक्टीरिया की मात्रा निर्धारित स्तर से काफी ज्यादा पाई गई।'**

पैसों से पानी खरीदने की व्यवस्था ने दुनियां के बड़े हिस्से को, जो गरीबी और लाचारी का जीवन जीने को अभिशप्त है, प्रदूषित और खतरनाक रासायनिक तत्वों से युक्त पानी पीते रहने और हैजा एवं अन्य घातक बीमारियां हमेशा-हमेशा भोगते रहने को मजबूर कर दिया है। **रासायनिक कीटनाशकों के अनियंत्रित प्रयोग ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। यह तत्व पेस्टीसाइड्स तथा अन्य कीटनाशकों के जरिए पानी, हवा और जमीन में घुल-मिल रहा है। आईटीआरसी के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में आर्सेनिक की विषाक्तता के सामान्य लक्षण चर्म रोग, आखों की लाली व खुजली, सांस संबंधी रोग आंत्रशोध देखे गए हैं। इसके पश्चात स्नायु रोग, यकृत रोग, चर्मरोग और त्वचा पर कालापन, मोटापा व धब्बेदार त्वचा द्वितीय अवस्था के लक्षण हैं। अंत में पैरों की त्वचा गलने लगती है। इसके साथ ही मुंह, जिह्वा, यकृत व पेट का कैंसर हो सकता है। स्मृति की गति धीमी पड़ जाती है। आर्सेनिक प्रभावित रोगियों में त्वचा का कालापन, मोटापा तथा धब्बेदार त्वचा सामान्य लक्षण हैं।**

पेयजल आपूर्ति का दायित्व निजी हाथों में सौंप कर सरकारें अपने दायित्व की इतिश्री कर ले रही हैं। एक ऐसा तत्व जिसके बिना जीवन ही असंभव है, निजी हाथों में पहुँचकर खरीद बिक्री और मुनाफा कमाने की वस्तु बनाया जा रहा है। पर्यावरण, समाज और मानवता के शाश्वत मूल्यों के खिलाफ जारी इस षडयंत्र को यदि समय रहते हुए

बेनकाब नहीं किया गया, प्रकृति की इस धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने के कारगर उपाय नहीं किए गए, रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग पर प्रतिबंध न लगाया गया, वनों के बेतहाशा विनाश को नहीं रोका गया, वृक्षारोपण अभियान को फाइलों से निकाल कर वास्तविकता की जमीन पर नहीं लाया गया, पानी दुरूपयोग को रोकने के लिए जन जागृति के सार्थक उपाय नहीं किए गए, तो वह दिन दूर नहीं, जब दुनिया में सर्वाधिक मौतें सिर्फ 'पीने के पानी के अभाव' के खाते में दर्ज होंगी। .... और तब हम विवश होंगे, बिल्कुल विवश, असहाय और लाचार।

* * *